



August 02, 2025

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001

Symbol: JUBLCPL

Scrip Code: 544355

Subject: Publication of information regarding 17th Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, August 26, 2025 through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means

Dear Sir(s),

This is to inform you that the 17th Annual General Meeting ('AGM') of Jubilant Agri and Consumer Products Limited ('the Company') is scheduled to be held on Tuesday, August 26, 2025 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means.

The Notice of the 17th AGM of the Company along with the Annual Report for the Financial Year 2024- 25 will be sent only to those shareholders whose email addresses are registered with the Company, Registrar and Transfer Agent, or Depository Participants, in due course. Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company will also send a letter providing the web-link, including the exact path of Annual Report to those shareholders whose email address is not registered with the Company/DP.

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of advertisements published today, i.e., August 02, 2024, in Mint (English) and Hindustan (Hindi), in accordance with the circular(s) issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India from time to time, informing about the 17th AGM of the Company and procedure for registering email addresses.

This is for your information and records.

Thanking you,

For **Jubilant Agri and Consumer Products Limited**

Hariom Pandey

Company Secretary

Encl.: a/a

A Jubilant Bhartia Group Company



Jubilant Agri and Consumer Products Limited

Plot. No. 142, Chimes, 3rd Floor, Sector 44,
Gurugram, Haryana - 122003, India
Tel: +91 124 2577229
www.jacpl.co.in

Regd. Office:
Bhartiagram, Gajraula
Distt. Amroha-244 223
Uttar Pradesh, India
CIN: L52100UP2008PLC035862
E-mail: investorsjacpl@jubl.com

सालाना 2,400 डॉलर का बोझ बढ़ेगा अमेरिकी उपभोक्ताओं पर अमेरिका पर ज्यादा असर पड़ेगा



नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर अमेरिका द्वारा 25 प्रतिशत का आयात शुल्क उसकी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा। शुक्रवार को एसबीआई रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि आयात शुल्क लगाने से स्वयं अमेरिका की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 40-50 आधार अंकों की गिरावट आ सकती है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में अमेरिका के इस कदम से डॉलर कमजोर पड़ सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अमेरिका की खराब व्यापार नीति है। इससे अमेरिका में घरेलू महंगाई और उपभोक्ता कीमतों पर ही नकारात्मक असर पड़ेगा। जबकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में खुद को समायोजित कर भारत को कुछ राहत मिल सकती है। ऐसे में आयात शुल्क लगाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारत से ज्यादा झटका

चिंता: फिलहाल जोखिम भरा होगा अमेरिका के खिलाफ जवाबी शुल्क

■ रोशन किशोर

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात से नाराज हैं कि अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है। उनका मानना है कि उच्च टैरिफ और गैर-मैट्रिक व्यापार बाधाओं के कारण ऐसा हुआ है।

ट्रंप ने भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 25% टैरिफ लगाने का येही मुख्य कारण बताया है। यह टैरिफ निश्चित रूप से नुकसानदेह होगा, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। हालांकि अमेरिका के खिलाफ जवाबी शुल्क लगाना भी फिलहाल जोखिम भरा है।

निर्यात में वृद्धि का बड़ा कारण

शुल्क की चिंता में बाजार दूसरे दिन भी फिसले

मुंबई, एजेंसी। अमेरिकी शुल्क संबंधी चिंताओं और वैश्विक बाजारों में व्यापक बिकवाली के बीच शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। संसेक्स 586 अंक घट गया जबकि निफ्टी में भी 203 अंकों की गिरावट दर्ज की गई।

विश्लेषकों के मुताबिक, अमेरिकी सरकार के 25 प्रतिशत शुल्क लगाने के ऐलान के बाद वैश्विक व्यापार में गतिरोध की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने भी धारणा को कमजोर किया।

For Enquiry
वलासीफाइड
 Rungbar: 950005979
 Whatsapp: 8041020061, 871271441
 Sambarh: 983765541, 934880882
 Ambarh: 997322456, 937730558

● ऋण/ आर्य

● ऋण/ आर्य

FUNDING FOR BUSINESS PEOPLE
5CR / NO UPFRONT CHARGES
ABOVE
CIBIL NOT REQUIRED
FLEXIBLE ROI WITH
REPAYMENT OPTION
48 HOURS EVALUATION

9176944434
email: pansyfin@gmail.com
website: www.pansy.co.in

● वित्तिसा एवं स्वास्थ्य श्रेणियाँ

● नाम परिवर्तन

● मैडिकल

सेक्स समस्याएँ
छोटेपन से निराश क्यों
400/- 600/-
नई खोज
18 से 80 वर्ष तक के लिए लाभदायक
चैन कर डालो से सलाह लें
गायत्री आयुर्वेदाश्रम
9572308520
9572308550

● नाम परिवर्तन

मैने अपने पुत्र विश्वनाथ कथूरिया को गलत सेगमें में पड़ जाने के कारण सम्बन्ध विच्छेद कर अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। उसके कृत्यों का वह स्वयं जिम्मेदार होगा। कश्मीरी लाल पुत्र रामरंजन नि.मै. कोलचुरी लह.व जिला संभलत।

भारत की अमेरिका पर निर्भरता कम हुई

हाल के वर्षों में कुछ अन्य देशों में भी भारत ने निर्यात को बढ़ाया है। हालांकि वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका 20 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारत का सबसे बड़ा निर्यात साझेदार रहा है, लेकिन शीर्ष 10 साझेदार देशों का कुल निर्यात में हिस्सा 53 प्रतिशत ही है। इससे भारत को अमेरिका पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न एवं आभूषण, दवाएं और मशीनरी शामिल है।

अमेरिका में हो सकती है जेनेरिक सस्ती दवाओं की किल्लत

भारत से जेनेरिक सस्ती दवाओं के निर्यात बाजार में अमेरिका की लगभग 47 प्रतिशत हिस्सेदारी है। अब अमेरिका इनका उत्पादन करता है या फिर दूसरे देशों से आपूर्ति करता है तो इसमें तीन से पांच वर्षों का समय लगेगा। ऐसे में अमेरिशियों को दवाओं की किल्लत और बढ़ी कीमतों का सामना करना पड़ सकता है।

लग सकता है क्योंकि हालिया फैसले से अमेरिका की जीडीपी में गिरावट, घरेलू स्तर पर महंगाई में उछाल और डॉलर कमजोर पड़ सकता है। अनुमान है कि



कुछ क्षेत्रों पर दिखेगा अधिक असर

डॉयचे बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री (भारत एवं दक्षिण एशिया) कोशिक दास ने कहा कि बिजली मशीनरी कलपुर्जे, रत्न, दवाएं, वस्त्र और रसायन जैसे क्षेत्र शुल्क से सर्वाधिक प्रभावित होंगे। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 43 अरब डॉलर हो गया है जो वित्त वर्ष 2012-13 में 11 अरब डॉलर था। चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारत का अमेरिका के साथ व्यापार 35.4 प्रतिशत बढ़कर 12.7 अरब डॉलर हो गया। इससे निर्यातकों को शुल्क समायोजित करने के लिए कुछ महीनों की मोहलत मिल जाएगी।

आयात शुल्क के कारण अमेरिकी उपभोक्ताओं पर सालाना औसतन 2,400 डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

इस समय जवाबी कार्रवाई से लाभ नहीं दिखाई देगा

जवाबी शुल्क लगाना दो कारणों से जोखिम भरा है। अमेरिका को भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण निर्यात (जैसे दवाइयां और दूरसंचार उपकरण) अभी भी शुल्क से मुक्त हैं और अमेरिका के खिलाफ कोई भी जवाबी कार्रवाई उन्हें खतरे में डाल सकती है। इस बात की गारंटी नहीं है कि ट्रंप इन छूटों को रद्द नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त, भारत को अमेरिका से गैर-व्यापारिक व्यापार मार्गों, जैसे कि प्रवासी आय और सेवा व्यापार से भी काफी लाभ होता है।

चीन+1: भारत की ओर से अमेरिका को निर्यात 2019-20 में 53 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 87 अरब डॉलर होगा। इस वृद्धि का 90% से ज्यादा हिस्सा अमेरिका को विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में है। लगभग 40% वृद्धि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में और 32% दूरसंचार उपकरणों में हुई है। इसका एक बड़ा हिस्सा भारत में बने आईफोन होने

की संभावना है। निर्यात में भारत की हालिया प्रगति किसी संरक्षणवादी रणनीति का नतीजा नहीं है, जैसा कि ट्रंप आरोप लगा रहे हैं। बल्कि यह चीन+1 रणनीति है, जिससे अमेरिका को होने वाले चीनी निर्यात कुछ हद तक भारत की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं।

Hindustan Times

आयात शुल्क दायरे से अभी बाहर है ईंधन का निर्यात

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले डीजल और विमान ईंधन जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को आयात शुल्क से छूट दी गई है। ट्रंप ने अभी यह संकेत नहीं दिया है कि रूस के साथ भारत के ऊर्जा व्यापार को रोकने के लिए वह कौन सा जुर्माना लगाने की योजना बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को जिस सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, वह केवल अमेरिका

आने वाले भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत शुल्क लागू करता है। इसमें ऐसे उत्पादों की भी सूची है, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इनमें तैयार दवा उत्पाद, औषधि निर्माण में उपयोग होने वाला कच्चा माल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी (सोफ्टवेयर, स्मार्टफोन) और पेट्रोलियम उत्पाद (कच्चा तेल, एलएनजी, परिष्कृत ईंधन, बिजली और कोयला) शामिल हैं।

कारखाना क्षेत्र की वृद्धि दर 16 माह की ऊंचाई पर

मुंबई, एजेंसी। भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर जुलाई में मजबूत होकर 16 महीने के उच्च स्तर 59.1 पर पहुंच गई। अनुकूल मांग परिस्थितियों के बीच नए ऑर्डर और उत्पादन में तेजी से इसे समर्थन मिला। शुक्रवार को मासिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जून के 58.4 से बढ़कर जुलाई में 59.1 हो गया। यह मार्च 2024 के बाद से इस क्षेत्र में सबसे मजबूत सुधार का संकेत है।

जुलाई में सकल जीएसटी संग्रह 7.5 फीसदी बढ़ा
नई दिल्ली, एजेंसी। सकल जीएसटी संग्रह जुलाई में 7.5 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.96 लाख करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से घरेलू राजस्व में वृद्धि के कारण जीएसटी संग्रह बढ़ा है। पिछले साल जुलाई में जीएसटी संग्रह 1.82 लाख करोड़ रुपये था। जून में यह 1.84 लाख करोड़ रुपये था। सकल घरेलू राजस्व 6.7 प्रतिशत बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि आयात से कर प्राप्ति 9.5 प्रतिशत बढ़कर 52,712 करोड़ रुपये रही। जीएसटी रिफंड सालाना आधार पर 66.8 प्रतिशत बढ़कर 27,147 करोड़ रुपये हो गया।

खोया- पाया

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा इन्टरमीडिएट वर्ष 2016 अनुक्रमिक 0827186 प्रमाणपत्र सहअंक पत्र वास्तव में खो गया है। मधु पुत्री रवेन्द्र सिंह नि.गांव रघुनाथ पीपरी,तहसील बिलसी जिला बदायूं।

बैंक आउट

मैने अपने पुत्र विश्वनाथ कथूरिया को गलत सेगमें में पड़ जाने के कारण सम्बन्ध विच्छेद कर अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। उसके कृत्यों का वह स्वयं जिम्मेदार होगा। कश्मीरी लाल पुत्र रामरंजन नि.मै. कोलचुरी लह.व जिला संभलत।

66 भारत के निर्यात पर कितना असर पड़ेगा, यह काफी हद तक अमेरिका जुर्माना निर्धारित किए जाने के बाद स्पष्ट होगा। वह भारत पर कूटनीति दबाव बनाना चाहता है, जिससे कि उसकी शर्तों पर भारत समझौता करने को तैयार हो जाए। - डॉ. अजय सहाय, महानिदेशक एवं सीईओ, फ़ियो

भारत के निर्यात पर कितना असर पड़ेगा, यह काफी हद तक अमेरिका जुर्माना निर्धारित किए जाने के बाद स्पष्ट होगा। वह भारत पर कूटनीति दबाव बनाना चाहता है, जिससे कि उसकी शर्तों पर भारत समझौता करने को तैयार हो जाए। - डॉ. अजय सहाय, महानिदेशक एवं सीईओ, फ़ियो

OFFICE MUNICIPAL COUNCIL CHOMU (JAIPUR)

Tel-01423-220036

e-mail:chomu.jaipur@yahoo.com

Sr. No. : NPC/2025/1400

Date : 30.07.2025

Notice Inviting Bid

Bids for "Sweeper Supply For Cleaning Work in Nagar Parishad Area Chomu" are invited interested bidders upto 12.00 PM on 31.07.2025 Dated. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.rajasathan.gov.in>, <http://sppp.raj.nic.in>) of the state.

NIB CODE : DLB2526A4114 & UBN NO. : DLB2526SLOB13092

Raj.Samwad/C/25/3739

COMMISSIONER

आम सूचना

हम आम जनता को सूचित करना चाहेंगे कि आईपी का मूल विलेख दिनांक 09.02.2017 जो की खसरा संख्या 16 मध्ये, ग्राम चकमेरी, तहसील विलासपुर, जिला रामपुर पर स्थित है। पूर्व में लिंक रोड, पश्चिम में नाला, उत्तर में आराजी कारत रामशेर सिंह आदि, दक्षिण में आराजी कारत विक्रमेगणा। बही नंबर 1, जियट 2498, पृष्ठ संख्या 207-244 दस्तावेज नंबर 571 पर सब रजिस्ट्रार विलासपुर पर पंजीकृत। श्री रामधारे भगत पुत्र श्री मुनेश्वर भगत के पक्ष में जो कि कहीं खो गए हैं और अप्राप्त हैं। इसके अलावा, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कार्यालय एम् सी सी हल्दानी, उपरोक्त संपत्ति को गिरवी रखने का इरादा रखता है। यदि कोई व्यक्ति इसे पाता है, या संपत्ति में किसी हित या स्वामित्व का दावा करता है, तो इस प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कार्यालय एम् सी सी हल्दानी से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

श्री जितिन कुमार एवं श्री जीतितन अरोड़ा पुत्रगण श्री करमचंद ग्राम नवाबगंज, तहसील विलासपुर, जिला रामपुर

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एक मुख्य विद्युत अभियान / निर्माण, उत्तर रेलवे, मुद्रादाबाद निम्नलिखित कार्य के लिए (एकल पैकेट प्रणाली) के अंतर्गत खुली ई-निविदा आमंत्रित करते हैं:-

1	ई-निविदा एनआईटी सं.	17-विद्युत / नि. / टी.आर.डी. / एम.बी. / 139-सी
2	कार्य का नाम व स्थान	मुद्रादाबाद मण्डल के रोजा-सीतापुर सिटी खण्ड में रोजा में क्रास ओवर शिफ्टिंग, लखनऊ-मुद्रादाबाद खण्ड में पीताम्बरपुर के कि.मी. 1288 / 17-19 पर गेट सं.-352 सी के बदले आराओबी, सीतापुर के कि.मी. 78 / 130.201 पर गेट सं.-51 स्पेलाल के बदले आराओबी, रोजा-सीतापुर सिटी खण्ड में डाउन मेंन लाईन के कि.मी. 14 / 305.923 पर पिछ सं. 13 एवं सेवरागिरी पोस्ट सीतापुर सिटी के विद्युतीकरण हेतु 25 हजार वोल्ट सिंगल फेज ओ.एच.ई. की डिजाइन, सप्लाई, इन्स्टाल, टेस्टिंग व कमीशनिंग का कार्य।
3	कार्य पूरा करने की अवधि	12 (बारह) माह
4	कार्य की अनुमानित लागत	रुपै 1,87,73,215.60
5	बगान राशि जो जमा की जानी है (निविदा दस्तावेज के खण्ड 3.0 के अनुसार)	रुपै 2,43,900 / -
6	ई-निविदा जमा करने एवं ई-निविदा खुलने की तिथि व समय	निविदा दिनांक 22.08.2025 समय 11:30 बजे तक आईआईपीएस की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं। निविदाकर्ता ई-निविदा में भाग ले सकते हैं। निविदा दिनांक 22.08.2025 समय 11:30 बजे खोली जाएगी।
7	निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र	विस्तृत ई-निविदा एवं निविदा प्रपत्र आईआईपीएस की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। उपरोक्त निविदा प्रपत्र आईआईपीएस की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर दिनांक 08.08.2025 से दिनांक 22.08.2025 तक जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा। निविदाकर्ता जो ई-निविदा में भाग लेने को इच्छुक हैं उनको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त वेबसाइट पर अपना ई-पंजीकरण करा ले जिसके लिए उन्हें क्लास III डिजिटल प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी (यदि पहले से उपलब्ध नहीं है), जो आई टी नियम-2000 के अंतर्गत सीसीए द्वारा जारी की जाएगी। उपरोक्त निविदा के अन्य सभी नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में दिये गये हैं। केवल ई-निविदाएं ही स्वीकार की जाएंगी तथा किसी अन्य रूप में प्रस्तुत निविदाएं तुरन्त अस्वीकार कर दी जाएंगी।

प्रपत्र सं: 17-विद्युत / नि. / टी.आर.डी. / एम.बी. / 139-सी दिनांक: 01.08.2025

ग्राहकों की सेवा में सुरकान के साथ

Nava Nalanda Mahavihara
(Deemed University)
 Ministry of Culture, Government of India
 Nalanda-803111, Bihar, INDIA

Advertisement for the Guest Faculty
Advt. Notice No. NNM/Guest Faculty/2025/02

Applications are invited from eligible Indian nationals for engagement as **Guest Faculty** for the academic session 2025-26 in various disciplines. For detailed qualifications, terms, conditions and application proforma, please visit: www.nnm.ac.in

Last Date for Submission: 18.08.2025 by 6:00 P.M.

Registrar
Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda

कार्यालय : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुद्रादाबाद

पत्रांक : एस0एस0ए0/प्रशिक्षण / 8213-19 / 2025-26 दिनांक :01/8/2025

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के पत्रांक : गुण0वि0 / ए0आर0पी0 / 9333 / 2024-25 दिनांक 15.01.2025, शासनादेश संख्या-68-5099/143/ 2024 बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 दिनांक 10 अक्टूबर 2024 एवं शासनादेश संख्या-902/68-5-2019 बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 के अनुक्रम में सप्ता शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड एवं नगर क्षेत्र में ए0आर0पी0 चयन हेतु बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक/30प्रा0/कम्पोजिट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाओं से ए0आर0पी0 पद हेतु आवेदन इस कार्यालय के पत्र सं0- एस0एस0ए0 / प्रशिक्षण / 2059-66/2025-26 दिनांक 25-06-2025 के माध्यम से दिनांक 10-07-2025 की सांय 5:00 बजे तक आमंत्रित किये गये थे। उक्त प्रेस विज्ञप्ति में दिये गये प्राविधानों के अनुसार आवेदन जमा करने की तिथि 14-08-2025 की सांय 5:00 बजे तक बढ़ाई जाती है।

(अखिलेश कुमार)
 प्रा0 जिला समन्वयक (प्रशिक्षण)
 मुद्रादाबाद

(विमलेश कुमार)
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
 मुद्रादाबाद

अधिकांश उत्पादों पर पहले से अमेरिका में शुल्क छूट

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 25 प्रतिशत शुल्क का भारत पर खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अधिकांश भारतीय वस्तुएं पहले से ही अमेरिकी शुल्क छूट की श्रेणी में आती हैं। सरकार से जुड़े सूत्रों ने शुक्रवार को यह अनुमान जताया।

इसके साथ ही भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी व्यापार समझौते में कृषि, डेयरी और जीएम खाद्य उत्पादों पर कोई शुल्क रियायत नहीं देगा। सूत्रों के मुताबिक, भारत के कुल निर्यात का बड़ा हिस्सा पहले ही अमेरिकी सरकार को रफ्त से सेक्शन 232 के तहत दी जाने वाली छूट के दायरे

प्ले स्टोर पर रियल मनी गेम की अनुमति मांगी

नई दिल्ली। भारत में रियल मनी गेम्स को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में एक बड़ा मोड़ आया है। म्हात ने गुगल प्ले स्टोर पर सभी वैध रियल मनी गेम्स को अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है।

किसी भी व्यापार करार में कृषि, डेयरी और जीएम उत्पादों पर कोई शुल्क रियायत नहीं देगा भारत

में आता है। ऐसे में उन उत्पादों पर बढ़ा हुआ शुल्क लागू नहीं होगा। सूत्रों ने कहा, भारत से अमेरिका को होने वाले आधे से अधिक निर्यात इस शुल्क वृद्धि से अप्रभावित रहेंगे। नई शुल्क नीति से लगभग 40 अरब डॉलर के निर्यात पर ही असर पड़ने की आशंका है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 131.8 अरब डॉलर रहा था।

में आता है। ऐसे में उन उत्पादों पर बढ़ा हुआ शुल्क लागू नहीं होगा। सूत्रों ने कहा, भारत से अमेरिका को होने वाले आधे से अधिक निर्यात इस शुल्क वृद्धि से अप्रभावित रहेंगे। नई शुल्क नीति से लगभग 40 अरब डॉलर के निर्यात पर ही असर पड़ने की आशंका है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 131.8 अरब डॉलर रहा था।

जुबिलेंट एग््री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 17वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत निर्मित नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 19 सितंबर 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 ('एससीए परिपत्र') के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों और सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 ('सेबी परिपत्र') और जारी किए गए अन्य लागू परिपत्रों और अधिसूचनाओं (किसी भी वैधानिक संशोधन या यथासमय लागू और संशोधित उसके पुनः अधिनियमन सहित) के अनुपालन में जुबिलेंट एग््री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के सदस्यों की 17वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय की पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा। एससीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से एजीएम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jacpl.co.in पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, यानी बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 36(1)(b) के अनुसार, जिन सदस्यों के ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें एक पत्र भेजा जाएगा, जिसमें उस वेब-लिंक का उल्लेख होगा जहां कंपनी की वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट अपलोड की गई है। उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। कंपनी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उन सदस्यों को भेजेगी, जो अपना फोनियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाईट आईडी का उल्लेख करते हुए investorsjacpl@jubl.com पर इसके लिए अनुरोध करेंगे। यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया investorsjacpl@jubl.com या rta@alankit.com पर डीपीआईआई-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईआई-सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाईट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें। इसके अलावा, सदस्य अपने संबंधित डीपी से अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करने का अनुरोध भी कर सकते हैं।

ई-वोटिंग: सदस्यों को एजीएम नोटिस में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम में) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग सुविधा की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम नोटिस में दी जाएगी। एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित थे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे।

31 मार्च, 2025 तक, 2,040 शेयरधारकों के कुल 65,339 इक्विटी शेयर कंपनी के नाम पर खोले गए डीमैट ससपेंस एक्को खातों में जमा हैं। इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक स्थगित रहेंगे जब तक कि इन शेयरों के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या दावा नहीं कर लेते। सदस्य कंपनी के डीमैट ससपेंस एक्को खातों से अपने शेयर जारी करवाने के लिए अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट से rta@alankit.com पर और कंपनी से investorsjacpl@jubl.com पर संपर्क कर सकते हैं।

सदस्य यह भी ध्यान दें कि सेबी के परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSDPoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसार, कंपनी के भौतिक शेयरों के हस्तान्तरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने की सुविधा के लिए 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोलना आवश्यक है। हालांकि, कंपनी के सभी शेयर डीमैट (अमृत) रूप में हैं, इसलिए उपरोक्त परिपत्र कंपनी पर लागू नहीं होता है।

जुबिलेंट एग््री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के लिए हस्ता./- हरिओम पांडे कंपनी सचिव

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति
पर्यावरण विभाग, (रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार)
5वीं मंजिल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-06
हमारी वेबसाइट देखें: <http://dpcc.delhigovt.nic.in>

नं. डीपीसीसी/(3)(2)(46)/एडमिन-19/20066 दिनांक: 01.08.2025

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में (i) प्रतिनियुक्ति द्वारा और (ii) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा विभिन्न पदों की भर्ती के लिए रोलिंग विज्ञापन

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित पदों को (i) प्रतिनियुक्ति द्वारा और (ii) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर भर्ने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

(ए) प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र/राज्य सरकारों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन:

क्र. सं.	पद का नाम	पद का
----------	-----------	-------